Speaking at Vyapari Sammelan in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh

January 08, 2017

किसी नेता ने व्यापारी वर्ग को चोर नहीं करार किया, कभी व्यापारी वर्ग की आलोचना नहीं की | हम सब वहां बैठे हुए हैं सरकार में, मैं खुद आपके समाज से हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, समाज में क्या मैं व्यापारी वर्ग से हूँ | और मैंने खुद लोहे की factory चलाई है, steel forging unit मैंने 18 वर्ष चलाई है तो मैं भली-भांति समझता हूँ कि मैंने भी बिजली का connection 1987 में कैसे लिया था, क्या खर्चा करके लिया था मुझे अभी तक याद है | तो इसको ही बदलने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और मैं समझता हूँ कि अगर इसको बदलना है तो उसके सबसे सरल तरीके दो हैं | एक तो हर एक चीज़ को shortages के बदले surplus बना दो, कैसे जो जो चीज़ों में कमी रहती थी उसको इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दो जिससे रिश्वत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग आपके पास आके बिजली बेचेंगे | और दूसरा पारदर्शिता, अगर हर एक चीज़ में हम सभी कुछ जानकारियाँ जनता के बीच रखें तो अपने आप में जनता को पता चलेगा कि बिजली भी उपलब्ध है, कोयला भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो काला बाजारी क्यों? और लगभग हमने दो-ढाई वर्षों में जो काम किये हैं बिजली के क्षेत्र में या कोयला के क्षेत्र में या नवीकरणीय ऊर्जा में हमारा कोशिश यही रही है कि बिजली इतनी पर्याप्त मात्रा में देश में उपलब्ध हो, कोयले की कभी कमी ना आने पाए किसी भी प्लांट में | और जो भी काम करें उसको पारदर्शिता से mobile app के द्वारा जनता तक पहुँचाना तो मेरे विभागों के जितने काम हैं वह सब आपको mobile app पे आपको भी मिल सकती है - कितनी बिजली मिल रही है, क्या दाम पे राज्य सरकार खरीद सकती है, कितनी बिजली के पॉवर कट आपके क्षेत्र में हो रहे हैं | हाँ यह अलग बात है कि दो महीने से उत्तर प्रदेश ने जानकारियाँ देना बंद कर दिया जब से उनको ध्यान आया कि mobile app पे सब जानकारी दे देते हैं तो जनता को और आक्रोश आता है |

और आज परिस्थिति यह है मैं पता लगा रहा था अपने कार्यालय से और यह हमारे app पे भी जानकारी पूरी आपको मिलेगी कि यह जो सरकार ने कहा कि यहाँ 24 घंटे शहरों में बिजली मिलेगी, 18 घंटे गावों में बिजली मिलेगी | उसके सामने जब वास्तु स्थिति निकाली तो ध्यान में आया कि शायद शहरों में भी आजतक 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, गाँव का तो हालत

एकदम ही खस्ता है और जब मैंने उद्योग की जानकारी निकाली तो उद्योग में तो पता चला अभी तक diesel generator पे ही ज्यादा करके काम चलता है या एक-आद shift चलती है | और आज परिस्थिति ऐसी है कि देश में लगभग 40,000 मेगावाट ऐसा है जो market ढूँढ रहा है, demand ढूँढ रहा है, जिसके पास power purchase agreement नहीं है, पर्याप्त कोयला है | आपकी जानकारी के लिए जब मैं ऊर्जा मंत्री बना तब देश में दो-तिहाई बिजली घर ऐसे थे जहाँ पे कोयले की कमी रहती थी किधर एक दिन, दो दिन, चार दिन का कोयला रहता था और जिसकी वजह से एक आंकड़ा report होता था रोज़ Electricity Authority द्वारा कि कितने यूनिट बिजली का loss हुआ कोयले के ना होने के कारण - loss of production because of shortage of coal.

मुझे आपको बताते हुए ख़ुशी होती है कि गत एक वर्ष में एक भी प्लांट, एक भी कोयले का बिजली घर ऐसा नहीं है जिसमें कोयले की एक दिन भी shortage हुई हो, not a single plant in the whole country. मैं मात्र उत्तर प्रदेश की नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में तो ज़रा भी नहीं है, पूरे देश में एक भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें कोयले की shortage है | उत्तर प्रदेश का आंकड़ा अभी अभी मैं लेके आया, लगभग 10 दिन से 36 दिन तक, 10 दिन से 36 दिन का कोयले का stock उत्तर प्रदेश के हर बिजली घर में है और उसकी details चाहिए हों तो मैं छोड़ के चले जाऊंगा | हर बिजली घर में कितना stock है वह details लेके आया हूँ मैं अपने साथ | परंतु इक्षा शक्ति चाहिए और इमानदारी चाहिए | आज दुर्भाग्य की बात यह है कि बिजली होने के बावजूद उत्तर प्रदेश बिजली खरीदता नहीं है और आपको बिजली देता नहीं है | आज भी उत्तर प्रदेश के जो losses हैं, जो technical losses या बिजली की चोरी मानते हैं, AT&C losses वह लगभग 33.82% है |

आप भाई साहब कह रहे थे 8 रुपये बिजली का दाम क्यों है? थोड़ी मात्रा में ज़रूर बिजली का दाम industry या commercial में ज्यादा होता है क्योंकि गरीबों को बिजली देनी है, खेतों में सस्ती बिजली देनी है, कुछ cross-subsidy समझ में आती है | लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में cross-subsidy होती है, पूरे देश में cross-subsidy होती है, पूरे देश में किसानों को, गरीबों को सस्ती बिजली दी जाती है | लेकिन उत्तर प्रदेश में जो महंगा दाम है उसके पीछे जो मूल कारण है वह यह है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको कभी बिजली का बिल देना ही नहीं पड़ता है और वह इलाके कौन से हैं वह आप सब जानते हैं मुझे खुलासा करने की ज़रूरत नहीं

है | वास्तव में अभी अभी 4-6 दिन पहले किसी ने WhatsApp message भेजा था बड़े बड़े आलिशान बंगले थे उसमें, वह एक-एक बंगला इतना बड़ा था कि मुझे लगता है उसके एक-एक का महीने का बिजली का बिल 10 लाख रुपये होना चाहिए इतने बड़े बंगले थे, और वह सब एक ही शहर में थे | हम साफ़-सफाई की बात करते हैं वह सिर्फ एक शहर की बात करते हैं | उसका नाम थोडा मिलता-जुलता है शायद |

पर हम चाहते हैं कि पूरे भ्रष्टाचार की साफ़-सफाई हो, सिर्फ एक गाँव में सिर्फ मुफ्त बिजली ना मिले | और ऐसी परिस्थिति में यह जो 33% का भार है यह जाके पूरा का पूरा एक प्रकार से उद्योग के ऊपर आता है और हमने कई schemes बनाई हैं जिससे यह भार कम हो सकता है | Feeder पे smart meter लगे तो पता चलेगा कौन से feeder से बिजली की चोरी हो रही है, कौन बिल दे रहा है कौन नहीं दे रहा है | यह जो झूठे notices की आपने बात कही इसका पता लगाना बहुत आसान है, 4-5000 रुपये का एक मीटर लगा दो हर feeder पे और उसके पैसे भी केंद्र सरकार पूरे देती है पता चल जायेगा चोरी किधर होती है | अब हमने देशभर में सब जगह यह कहा है कि जहाँ जहाँ चोरी रुकती है, बंद होती है वहां चौबीस घंटे सुनिश्चित कर दो |

तो मुझे आपको बताते हुए ख़ुशी होती है, हरयाणा आपसे लगा हुआ ही है, हरयाणा | हरयाणा में पंचकुला आपने सुना होगा, पंचकुला के उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र और घरेलू सभी ने मिलके तय किया कि हम सब चोरी को रोकेंगे, अगर कोई चोरी करता है तो complain करेंगे और उनकी पूरी AT&C losses इतनी कम हो गयीं कि आज पहली जनवरी से पूरे पंचकुला, हर उद्योग को, 173 गावों को 24 घंटे बिजली आज पंचकुला में मिल रही है | और दक्षिण हरयाणा का जो DISCOM है वह loss करने वाला DISCOM पिछले साल तक इस 6 महीने में 213 करोड़ रुपये का उसने profit किया है | जितनी बिजली ज्यादा देंगे उद्योग को उतना ज्यादा profit होगा DISCOMs का और यह जो उत्तर प्रदेश के DISCOMs आज 10,000 करोड़ का सालाना loss करते हैं इस loss का तो कारण हमें समझ नहीं आता है |

और कहाँ बात हो रही है चौबीस घंटे बिजली देने की मैं आंकड़े निकाल रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी 1,80,00,000 घर हैं, संजीव जी 1,80,00,000 घर हैं जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है, 1,80,00,000! और इन सबको खास-तौर पे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको मुफ्त में बिजली देने के लिए केंद्र सरकार की योजना से शत-प्रतिशत पैसे मिलते हैं | उसके

बावजूद यहाँ की राज्य सरकार और मैंने जब आंकड़े निकाले कि गत 10, 4-5 वर्षों, 10 वर्षों में क्या हुआ तो आपको जानके हैरानी होगी कि लगभग, जब मैं मंत्री बना 2014 में, तब 11,000 crore sanctioned पैसे पड़े थे उत्तर प्रदेश के पास केंद्र के | मैंने आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7,000 करोड़ और दिए तो 18,000 करोड़ हो गए लेकिन जो जो काम करने के लिए उनकी ज़रूरत थी, जो उनको करना था उसको करने के लिए पूरी तरीके से राज्य सरकार सक्षम नहीं है, तैयार नहीं है, चाहती नहीं है, इक्षा शक्ति नहीं है |

और जब मैंने आंकड़े निकाले तो आपको भी आंकड़े देख के हैरानी होगी कि ग्रामीण क्षेत्र में नए गावों तक बिजली पहुँचाने का काम 2009-10 में पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 56 गावों में बिजली लेके गए, 2009-10 में; 2010-11 में मात्र 23 गावों में और 2011-12 में 0 गावों में | यह 3 वर्ष एक सरकार थी यह था track record - 56, 23 और 0 | दिल्ली में कांग्रेस की सरकार और यहाँ पे बसपा की सरकार |

अब 2012 में आई सपा की सरकार, क्या परिस्थिति में बदलाव हुआ - 2012-13 में मात्र 3 गावों में बिजली पहुंची, 2013-14 में फिर 0, फिर 2014 में हमारी सरकार दिल्ली में आई तब हमने लगाम कसी, तब निगरानी बढाई, पैसे के खर्च में गुणवत्ता देखी | तब जाके 2015-15 में 1305 गावों में बिजली पहुँचाने का काम हमारे ग्रामीण वियुतीकरण अभियंता के रोज़ के monitoring और follow-up के बाद हो पाया | हाँ यह बात अलग है कि गाँव में बिजली पहुंचाई, गाँव में बिजली पहुँचाने का हमें certificate भेज दिया, 6-6 अफसरों से sign करके नगला फटला का certificate भेजा था दिल्ली में | और उसके पैसे की claim भेज दी कि हमें पैसा दो हमने बिजली पहुंचा दी है | जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त लाल किल्ले से बताया कि नगला फटला में बिजली पहुँच गई तब असलियत की जानकारी मिली कि बिजली के पैसे का claim भेज दिया, बिजली के लाइनें लग गई, energize कर दिया transformer को, कुछ 29 नवम्बर या कोई तारीख को, 29 नवम्बर 2015 को और अगले दिन से बिजली काट दी, देनी बंद कर दी | और फिर चोरी के जो connections चल रहे थे बस मात्र वही connection चलते थे अब ऐसी परिस्थिति में कब आपका बिल कम होगा वह तो भगवान् ही जाने | अगर इस प्रकार से सरकार काम करेगी कि चोरी encourage करना और जो official connection जिसके लिए केंद्र सरकार पैसे देती है उसमें बिजली ना देना यह तो इस सरकार की प्राथमिकता रही, यह इस सरकार का काम करने का ढंग रहा |

मैं निकाल रहा था आंकड़े 30 गुनाह ज्यादा इस प्रदेश में power cut होता है, 30 गुनाह, बाकी राज्यों से जो अच्छे राज्य हैं | 90 घंटे तक बिजली जाती है, outages 90 घंटे तक होते हैं प्रमुखतः शहरों में और बिजली की चोरी लगभग 44% चोरी की जानकारियाँ मिलती हैं | और वैसी परिस्थिति में बिजली जो मिल भी रही है उसको भी कैसे सुचारू रूप से सबको दी जाये, सबको अच्छे rates पे दी जाये जो affordable हो, जिसपे लोगों को चोरी करने का प्रोत्साहन ना मिले यह एक अच्छे राज्य सरकार का दायित्व बनता है |

मुझे आपको बताते हुए ख़ुशी होती है कि प्रधानमंत्रीजी जिस राज्य से आते हैं गुजरात वहां पे भी परिस्थिति बहुत गंभीर थी, 2002 में जब वह मुख्यमंत्री बने, उस समय 2.5 हज़ार करोड़ का loss था गुजरात में 15 साल पहले लेकिन .....

... बड़ा उद्योग हो, कौन आएगा यहाँ के भ्रष्टाचार में, कौन आएगा यहाँ के जो कानून व्यवस्था है उसको देख के, कोई साधारणता देश में इतने अलग अलग जगह उद्योग लगाने के लिए encouragement मिलती है | उत्तर प्रदेश को अगर नया उद्योग लाना है, बड़ा उद्योग लाना है और बड़े उद्योग के साथ ancillary industry पनपती है - लोहे का व्यापार, electricity के ancillary units, बाकी जितने अपने व्यापारी अलग अलग प्रकार के काम होते हैं व्यापारियों के वह सब पनपते हैं जब बड़ा उद्योग आता है, सीधा रोज़गार तो बनता ही है indirect employment बहुत बड़ी मात्रा में आता है |

तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश भी अपना सोच बदले, सरकार बदले और एक नए रूप से भ्रष्टाचारमुक्त उत्तर प्रदेश जिसमें कानून व्यवस्था अच्छी हो, सुचारू रूप से हो, जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, व्यापारियों का शोषण ना हो, इस प्रकार की एक सरकार और वह सरकार भारतीय जनता पार्टी के इलावा इस प्रदेश को और कोई नहीं दे सकता | प्रधानमंत्री मोदीजी ने GST लाया था, GST का कानून, आखिर GST कैसे सफल हो सकता है जबतक काला बाजारी और काला धन का व्यापार बंद नहीं होगा | आज परिस्थिति यह है कि व्यापारी इमानदार होना भी चाहे तो कई बार व्यवस्था उसको इमानदार होने नहीं देती, अधिकारीगण जो व्यवस्था tax के अधिकारियों की है जो local inspectors की व्यवस्था है वह एक आदमी को इमानदार व्यापार नहीं करने देना चाहती और साथ ही साथ जब दो-तीन व्यापारी, कोई भी समाज में जब दो-तीन व्यापारी चोरी करते हैं तो competition unequal हो

जाती है, अहिस्ते अहिस्ते पूरे समाज को, पूरे व्यापारी वर्ग को उस competition को सहन नहीं कर सकते हैं तो अहिस्ते अहिस्ते उनको भी जुड़ना पड़ता है गलत कामों में |

मैं समझता हूँ नोटबंदी का जो यह फैसला हुआ, यह जब बात होती है कि भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, जब बात होती है कि काला बाजारी ख़त्म करनी है तो यह हम सबको लाभ देने के लिए करी गयी है | यह ऐसा नहीं है कि यह कोई हमारे खिलाफ कोई कदम है, कोई व्यापारी वर्ग के खिलाफ नहीं है, व्यापारी वर्ग का काम सरल करने के लिए किया गया है | आखिर आपने देखा होगा 2 करोड़ रुपये तक के turnover वालों के लिए अब एक presumptive tax की scheme लायी गयी है, आपको कोई किताब नहीं रखना, कुछ नहीं, कोई tax का अधिकारी आपको कुछ पूछ नहीं पायेगा | आपकी income 8% turnover की मानी जाएगी तो 2 करोड़ का जिसका sale है उसकी income ही सिर्फ 16 लाख मानी जाएगी, चाहे आपकी income ज्यादा हो कितनी भी हो, presumptive tax में 16 लाख मानी जाएगी |

अभी अभी वित्त मंत्री ने एक नया उसमें संशोदन किया कि अगर आप इसको डिजिटल माध्यम से करो और डिजिटल माध्यम की और सुविधाएं तेज़ी से बढती जा रही हैं | अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने भीम app का भी launch किया, भीम app से तो mobile-to-mobile बिना कोई machine के भी आप व्यापार कर सकते हैं, पैसे का लेन-देन कर सकते हैं, बड़े सरल तरीके से, internet की भी आवश्यकता नहीं, एक 800 रुपये के feature phone से भी व्यापार हो सकता है | इतना सरल यह BHIM App – Bharat Interface for Money, बाबा साहेब आंबेडकर जी के नाम पे रखा गया | और अलग अलग प्रकार से Rupay card हो, Aadhar-enabled payment system हो, digital को promote करने के लिए सरकार कदम उठा रही है | अब आप अगर दो करोड़ तक के व्यापारी हो और digital माध्यम से आप अपना पूरा व्यापार करो तो आपकी 8% के बदले मात्र 6% income मानी जाएगी | और मैंने calculate किया कि जो जो exemptions available हैं, आप Provident Fund में डालो तो कुछ exemption है, आप घर खरीदते हो तो कुछ exemption है, आप fix deposit में कुछ रखते हो तो exemption है | तो जो अलग अलग प्रकार की exemptions हैं, बजट में देखते हैं क्या नया रूप आता है, क्या और सुविधाएं जनता को मिलती हैं, व्यापारियों को मिलती हैं | और मैं समझता हूँ इमानदारी के रस्ते पे जाने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एकदम ही संकल्पित हैं उसी लिए उन्होंने कहा कि digital transaction पे मात्र 6% हम आपकी आय

गिनेंगे | तो आप calculate करिए दो करोड़ का turnover, income गिनी जाएगी मात्र 12 लाख, 12 लाख में भी 7.5 लाख रुपये तक exemptions गिनके लगभग कोई tax नहीं लगता है | यहाँ कोई chartered accountant है तो वह confirm कर देगा, 2.5 लाख तक तो आपको exemption है बाकी 5 लाख तक अलग अलग exemption मिलती है mediclaim, बच्चों की पढाई, वगैरा वगैरा | तो उसके बाद जो tax रह जायेगा दो करोड़ turnover वाले का, मात्र 65,000 रुपये, अब आप बताइये 65,000 देना क्या चुभेगा किसी को, 65,000 दो करोड़ के turnover पे, बिना कोई किताब रखे, बिना कोई पूछताछ के | और जब मैं उसको अलग अलग levels पे देख रहा था साधारणता एक खुदरा व्यापार करने वाले का तो Rs 50-60 लाख का सेल महीने का Rs 3-4 लाख से ज्यादा नहीं होता है, उसको तो लगभग साल में 5,000 रुपये टैक्स आएगा, 5,000 रुपये सिर्फ, पूरे साल की आमदनी पे |

तो मेरे खयाल से एक हमें सुनहरा मौका है हम सबको इमानदारी का रास्ते में जुड़ने का, इमानदारी से काम करने का और अगर पूरा व्यापारी समाज यह द्रण निश्चय कर ले कि हम सब इमानदारी से काम करेंगे तो tax का आय जो राजस्व collect होता है वह भी बढेगा, वह बढेगा तो tax के rates घट सकते हैं | आखिर हम सबकी एक चिन्ता रहती हैना कि GST आया लेकिन tax की rates ना बढे, और ज्यादा ना बढे, वह बढ़ते क्यूँ है? आज World Bank कहता है कि 20% भारत की economy कागजों पे है ही नहीं, cash में होती है, नंबर 2 में होती है, अलग अलग आंकड़े हैं, कुछ लोग तो कहते हैं 30 या 40% informal economy है | अब यह पूरी economy अगर formal economy में आ जाये उसका बहीखाता पूरा रखना शुरू हो जाये तो आप समझये राजस्व कितना बढेगा और tax के rate कम करने की कितनी हमारी पास क्षमता होगी और तब सबका व्यापार equal हो जायेगा, opportunity सबको equal मिलेगी, तब competition आपकी गुणवत्ता पे होगा, quality of service और quality of goods उसके ऊपर आपका competition होगा बजाये कि tax कौन ज्यादा चोरी कर सकता है, उसकी गुणवत्ता पे उसको व्यापार करने की सुविधा होगी |

तो मैं समझता हूँ इस नोटबंदी के फैसले को कोई अन्यथा ना ले | अभी हमारी तरफ से कोशिश है कि Rupay card जो Aadhar-based payment system है, जो Bhim App से payment होगी इसके charges को भी बहुत कम कर देता है | आज Rupay card पे शायद .5% charges लगते हैं, आप credit card से mix up ना करिए, credit card में आप credit देते हो

उपभोक्ता को, उसके charges से सरकार अपना व्यापार नहीं करती है, अपना तय नहीं करती है वह credit card और दुकानदार के बीच में है | लेकिन debit card के charges घटा के अब .5% कर दिए गए हैं और आगे आने वाले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और कम किया जाये, Bhim App के माध्यम से और Aadhar payment system के माध्यम से कैसे charges को और घटाया जाये जिससे digital transaction करने में लोगों को सुविधा हो, खर्चा ज्यादा ना पड़े और लोगों को यह confidence हो कि उनका व्यापार के ऊपर कोई इंस्पेक्टर राज नहीं लगेगा, उनको कोई परेशान नहीं किया जायेगा, कैसे सरलता लाई जाये, सरलीकरण किया जाये कानूनों का और कैसे इन tax के rates को भी एक प्रकार से affordable बनाया जाये |

और एक बहुत बड़ा आश्वासन मान्य प्रधानमंत्री ने पूरे देश के व्यापारियों को दिया है | हो सकता है 8 नवम्बर के पहले कोई न कोई कारण से आपको दुविधा रही हो या आपको इमानदार रास्ता अपनाने के लिए दिक्कत रही हो | प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है income tax, excise department और labour deparment, तीनों ने notification निकाले हैं कि पुराना postmortem नहीं किया जायेगा | जो भी इमानदारी के रास्ते पे अब आयेगा और इमानदारी के रास्ते से व्यापार करेगा उसका पुराना postmortem, पुराने खाते नहीं खोले जायेंगे | आप सबको आमंत्रण है कि आप इमानदारी के रास्ते पे चलें | Opposition आज बड़ी दुविधा में है, नोटबंदी को लगभग पूरे देश ने स्वीकार किया है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यह कठिनाई भी सहन की है | मैं जानता हूँ कि लोगों को कठिनाई हुई और मैं एक प्रकार से संजीव जी और प्रधानमंत्री जी और हम सबकी तरफ से पूरे आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने कष्ट और कठिनाई के बावजूद इस भ्रष्टाचार और काले धन के इस खिलाफ कदम का समर्थन किया है, आशीर्वाद दिया है | और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब 500 के नोट तो बहुत बड़े पयमाने पे इस हफ्ते भी आये हैं अगले 2-3 हफ्ते में बहुत बड़े पयमाने पे आयेंगे | पहले हम 2000 के नोट ज्यादा निकाल रहे थे क्योंकि चाह रहे थे कि पैसा सबको उपलब्ध हो जाये, अब 500 के नोट बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में आ रहे हैं | 100 और उसके छोटे नोट तो आज भी इतने हैं कि अवसद देश में अगर 25 करोड़ परिवार हैं तो लगभग 15,000 रुपये हर परिवार के पीछे आज 100 और उससे छोटे denomination के notes available हैं पूरे देशभर में | तो एक बार 500 के नोट आने के बाद और स्थिति में बहुत सुधराव हो जायेगा, ATM की

भी limit 4,500 कर दी गयी है, व्यापारियों की limit 50,000, ज़रूर कम है मैं वापिस जाऊंगा वित्त मंत्री से भी बात करूँगा, इसको भी बढाने की हम कोशिश करेंगे जल्द |

लेकिन अगर हम डिजिटल माध्यम से अपना व्यापार बढाते हैं और अभी तो डीजी, व्यापार बढाने के लिए डीजी-धन मेले में भी पूरे देशभर में आयोजित किये जा रहे हैं | अभी अभी मेरठ भी हुआ था, 4 तारीख को मेरठ में एक बहुत सुन्दर आयोजन हुआ मेले का, हर रोज़ 15,000 लोगों को lucky जो ग्राहक हैं, डीजी-धन मेला के माध्यम से, जो lucky ग्राहक हैं उनको लगभग 15,000 लोगों को रोज़ और व्यापारियों को हर हफ्ते इनाम दिए जायेंगे एक प्रकार से डिजिटल व्यापार से जुड़ने के लिए | तो मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से पूरा प्रयत्न हो रहा है कैसे व्यापारी को इमानदार होने के रास्ते पे मदद की जाये और जहाँ तक लेबर की बात आपने उठाई, मैं समझता हूँ देखिये लेबर को health benefit मिले, उसकी social security वृध्दावस्था में उसकी social security provident fund के माध्यम से हो, यह एक तरीके से समाज का दायित्व है, यह हम सबका दायित्व है | हमने कोशिश करनी चाहिए कि लेबर को उसका इमानदारी से न्यूनतम तनखा मिले, minimum wages मिले और ESI PF का benefit मिलता है तो उसके पूरे परिवार की स्वास्थय सेवा भी दी जा सकेगी | Cost ESIC का 4% है, अब आप सोचिये 4% तनखा अगर हम देते हैं तो 10,000 आपने कहा तो 400 रुपये हो गए, employee के ऊपर 175 रुपये लगते हैं | हाँ लेकिन यह बात मैं आपकी लेके जा रहा हूँ कि ESI facility यहाँ पे और सुधारी जाये वह मैं आपकी बात ज़रूर लेबर मंत्रालय से बात करके सुधार करने में हम लगेंगे | वह दायित्व आप हमें दीजिये कि मजदूर को कैसे सुविधा अच्छी मिले और पूरे परिवार को उसको कैसे मुफ्त में स्वास्थय की सुविधा मिले वह हम सब व्यापारियों ने उसके लिए लड़ना चाहिए, हम उसके लिए काम करेंगे | State government तो अब मात्र एक महीने की, डेढ़ महीने की मेहमान है उसके बाद तो आप लोगों का फैसला सामने आ ही जायेगा चुनाव के बाद |

और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसमें हम उत्तर प्रदेश में सुधार लायेंगे, कैसे स्वास्थय सेवाएं, कैसे शिक्षा की सेवाएं सुधरें जिससे मजदूर भाई बहनों को भी एक अच्छा जीवन बिताने के लिए quality of life जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने कहा हर एक व्यक्ति की सुधर सके | एक आखरी में मैं ज़रूर यह बताना चाहूँगा जिस प्रकार से व्यापारियों का उत्पीडन हुआ है, शोषण हुआ है गत 15 वर्षों में, भाजपा आपकी सरकार है, आपने सदियों से भाजपा का साथ दिया है और यह साथ

हम निभाएंगे कभी भूलेंगे नहीं यह मैं आपको पर्सनल आश्वासन देके जा रहा हूँ | और आपके ऊपर कोई इंस्पेक्टर राज नहीं लगेगा, हम उलटे सरलीकरण करके इंस्पेक्टर राज खत्म करना चाहते हैं | अगर किसी को 50,000-1 लाख रुपये पे notice आये हैं तो आप संजीव जी को notice दीजिये मैं देखना चाहूँगा कोई सवाल ही नहीं होता | Notice कब आता है वह भी बता दो, अगर किसी की सालाना आय, income tax में सालाना आय कोई बोलता है मेरी 5 लाख रुपये है और अकाउंट में 2 करोड़ रुपये जमा करता है, 1 करोड़ रुपये जमा करता है तो आप बताइये notice आएगा कि नहीं आएगा? तो notice आने के पहले छानबीन की जाती है और गलती से किसी को notice आ भी गया तो एक चार लाइनों की चिट्ठी लिख दे मैं किसान हूँ, यह मेरी किसान की आमदनी है, मेरा 4 acre की ज़मीन है, 8 acre की ज़मीन है, अपने आप बात ख़त्म हो जाएगी | कोई व्यापारी है लिखे मेरा व्यापार का काम है, इतना turnover है, यह मेरा PAN Number है, कोई पूछताछ नहीं होगी |

आप जवाब दे दीजिये अगर कोई भी harassment होगी, संजीव जी को बोलिए, सीधा मुझे फ़ोन करेंगे, सीधा मुझे फ़ोन आएगा | तो आप लोग चिन्ता ना करें, आप लोग खड़े रहें और अगर कोई harassment होती है कोई अधिकारी से तो तुरंत जानकारी हमें मिले तो हम उस पे action ले सकते हैं |

मैं अंत में सिर्फ एक आप से request करके जाऊंगा, कुछ करने की इक्षा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है | और अगर हम सब इमानदारी के रास्ते पे जाना चाहें, हम सब इमानदारी के रास्ते को अपना लें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे लिए किसी के लिए भी चाहे व्यापारी भी चाहे राजनीतिक नेता हो, किसी के लिए भी इमानदारी का रास्ता असंभव नहीं है, इमानदारी का रास्ता अपनाया जा सकता है | बदलाव में शुरू में थोड़ी तकलीफें आती हैं पर यह तकलीफें अगर हम झेलने के बाद इमानदारी के रास्ते में सब लोग लग जायें तो यह रास्ता सरल भी है, यह रास्ता चैन की नींद देता है रात को | और जो नयी युवा पीढ़ी है, नयी युवा पीढ़ी यह पुराने काम-धंधों में नहीं पड़ना चाहती | मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ आप घर जाके अपने बच्चों से पूछिए, क्या वह इस प्रकार से व्यापार करना चाहते हैं? या छोटा-मोटा टैक्स देके एक शान का जीवन जीना चाहता है | और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो 65% इस देश का युवा है वह युवा इमानदारी का रास्ता, सुख-चैन की नींद और एक देश का अच्छा नागरिक बनके जीना चाहता है | और हमारा व्यापारी वर्ग यह प्रण लेले कि हम सब

इमानदारी के रास्ते पे चलेंगे, अगर हम में से कोई गलत रास्ता करेगा तो हम उसकी जानकारी सरकार को देके उसके ऊपर action कराएँगे जिससे इमानदार पे action नहीं होगा, बेईमान पे action होगा | और मैं समझता हूँ नोटबंदी का फैसला पहली बार इमानदार को सम्मान देता है और बेईमान का नुक्सान करता है | अब हम तय कर लें हमको इमानदार बनना है .....

....आपके नाम के साथ लेंगे और पूरे राजनीतिक क्षेत्र में भी एक पारदर्शिता और इमानदारी भाजपा से शुरू करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने एक इमानदार शासन अलग अलग, देश में अलग अलग राज्यों में दिया है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी एक भ्रष्टाचारमुक्त कानून व्यवस्था का सन्मान करने वाला, महिलाओं का शोषण बंद करने वाला और गरीबों को एक अच्छे हक दिलवाने वाला, गरीबों के जीवन को सुधार करने वाला ऐसा शासन भारतीय जनता पार्टी का जल्द ही आने जा रहा है | मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आप सबका सहयोग लेने आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है पूरा व्यापारी वर्ग भाजपा के साथ खड़ा है, भाजपा के समर्थन में खड़ा है और हम सब मिलके इस देश में एक नया प्रणाली, काम करने की प्रणाली स्थापित करने में सफल हूंगे | आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आपके साथ खड़े हैं |

मैंने जैसे बताया बिजली के rate में जब चोरी कम होती है तो अपने आप स्वाभाविक है rate कम होंगे और आज 2.5 रुपये, 3 रुपये में.... मैं अभी अभी देख रहा था कल की जानकारी, कल power exchange में 2.5 रुपये में बिजली जितनी चाहिए, 2.72 रुपये में परसों और कल 2.57 रुपये में बिजली उपलब्ध थी | तो आज इस प्रदेश में हर एक को चौबीस घंटे बिजली मिल सकती है, सस्ती बिजली लेके DISCOM आपको दे सकती है | और जब 14,000 MW के बदले 25,000 MW लेंगे तो अपने आप बिजली के दर कम हो सकते हैं, क्योंकि fix cost, हम तो सब व्यापारी हैं, fix cost हमारा same रहता है | जब बिजली डबल हो जाएगी तो खर्चा आधा हो जायेगा | और यह जो 1 करोड़ 80 लाख घरों में आज भी बिजली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के हर घर में चौबीसों घंटे बिजली और किसानों को पर्याप्त बिजली हम देंगे यह हमारा एकदम पक्का आपको विश्वास है, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके सुनिश्चित करेंगे |

बहुत बहुत धन्यवाद |

एक सुझाव आया है कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में भी किया जाये, जैसा मध्य प्रदेश, जैसे पंजाब, जैसे हरयाणा ने किया है इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी | और व्यापारी और सरकार मिलके सुधार के पीछे लगेंगे |

बहुत बहुत धन्यवाद |